UNIVERSITY NEWS 11 OCTOBER 2025

AMAR UJALA PAGE NO 7

यूपी ट्रेड शो में सजावटी सामान की खूब हुई बिक्री

लखनऊ। लखनऊ विश्वविद्यालय में सजे यूपी ट्रेड शो स्वदेशी मेले के दूसरे दिन शुक्रवार को सजावटी सामान की खूब बिक्री रही। कैंडल और खानपान में मोम पापड़ी और नमकीन स्टॉल पर भी अच्छी भीड़ रही। अटायर ब्रांड के कपड़े के स्टॉल और मॉक टॉयज के स्टॉल से लोगों ने अच्छी खरीदारी की। उपायुक्त उद्योग मनोज चौरसिया ने बताया कि धीरे-धीरे सकारात्मक रुझान मिलते जा रहे हैं। क्योंकि यह जगह शहरवासियों के लिए काफी मुफीद है। (संवाद)

राजधानी के सिद्धांत इटली में प्रस्तुत करेंगे शोध

लखनऊ। लविवि के भू-विज्ञान विभाग के शोध छात्र सिद्धांत वैश्य को अंतरराष्ट्रीय सम्मान मिला है। उन्हें द माइक्रोपैलियोलॉजिकल सोसाइटी की ओर से ट्रैवल ग्रांट अवॉर्ड दिया गया है।

सिद्धांत अब इटली के पीसा विश्वविद्यालय में होने वाली वार्षिक बैठक में हिस्सा लेंगे, जहां वे भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे और शोध प्रस्तुत करेंगे।

उनके शोध का विषय काजीरंगा नेशनल पार्क की मोना झील में मिट्टी के कणों और परागकणों का अध्ययन और उसका प्राचीन पर्यावरण व बाढ़ के इतिहास से संबंध है।

इस सम्मान के लिए पूरे भारत से दो शोधकर्ताओं का चयन हुआ है, जिनमें से एक सिद्धांत हैं। वे पीएचडी शोध कार्य लविवि के प्रो. अजय कुमार आर्य और बीरबल साहनी पुरविज्ञान संस्थान की डॉ. साधना कुमार बासुमतारी के निर्देशन में कर रहे हैं। (माई सिटी रिपोर्टर)

यूपी ने कर संग्रहण में किया सुधार

लखनऊ। लविवि के अर्थशास्त्र विभाग के डॉ. नागेंद्र कुमार मौर्य और डॉ. करुणा शंकर कनौजिया ने उत्तर प्रदेश के वित्त का मूल्यांकन विषय पर रिपोर्ट तैयार की है। इसमें बताया गया है कि राज्य ने कर संग्रहण में सुधार किया है, लेकिन इससे जीएसडीपी अनुपात अब भी सात से आठ फीसदी के बीच है। पूंजीगत निवेश बढ़कर कुल व्यय का लगभग 28 प्रतिशत हो गया है, जिससे वित्तीय योजना में बुनियादी ढांचे, शिक्षा और स्वास्थ्य पर फोकस बढ़ा है। यह अध्ययन 16वें वित्त आयोग के लिए किया गया है। इसमें वर्ष 2012-13 से 2023-24 तक की वित्तीय स्थिति का विश्लेषण किया गया है। (माई सिटी रिपोर्टर)

डॉ. हेमेंद्र बनाए गए नोडल अधिकारी

लखनऊ। लविवि के कुलपति ने शिक्षा शास्त्र विभाग के एसोसिएट प्रो. डॉ. हेमेंद्र कुमार सिंह को चौथे राष्ट्रीय पर्यावरण युवा संसद 2026 के लिए पर्यावरण नोडल अधिकारी नामित किया है। कार्यक्रम का आयोजन वसुधैव कुटुंबकम और ग्रीन यूथ लीडरशिप की भावना के साथ होगा। (माई सिटी रिपोर्टर)

HINDUSTAN PAGE NO 7

मानसिक कल्याण के लिए समर्थन की जरूरत

लखनऊ। लखनऊ विवि की हैप्पी थिंकिंग लेबोरेटरी और काउंसलिंग एंड गाइडेंस सेल ने विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस पर अपलिफ्ट योरसेल्फ : टुगेदर फॉर मेंटल वेलनेस जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। कुलपति प्रो. मनुका खन्ना, डीन स्टूडेंट वेलफेयर प्रो. वीके शर्मा और एचटीएल निदेशक प्रो. एम. प्रियदर्शिनी और सीजीसी निदेशक प्रो. वैशाली सक्सेना समेत अन्य कार्यक्रम में मौजूद रहे।

AMRIT VICHAR PAGE NO 8

लविवि के शोधार्थी सिद्धांत वैश्य इटली के पीसा विश्वविद्यालय में प्रस्तुत करेंगे शोध पत्र

- अमृत विचार, लखनऊ : लखनऊ विश्वविद्यालय के भूविज्ञान विभाग के शोध छात्र सिद्धांत वैश्य को बिरबल साहनी पुराविज्ञान संस्थान के साथ संयुक्त रूप से द माइक्रोपैलियोलॉजिकल सोसाइटी द्वारा प्रतिष्ठित ट्रैवल ग्रांट 2025 से सम्मानित किया गया है। वे इटली के पीसा विश्वविद्यालय में होने वाली वार्षिक बैठक 2025 में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। सिद्धांत अपने शोध पत्र काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की मोना झील में कण आकार और परागकण संचयन का पैटर्न तथा इसका प्राचीन पर्यावरण और बाढ़ विश्लेषण पर प्रभाव पर प्रस्तुति देंगे। इस अंतरराष्ट्रीय सम्मान के लिए भारत से केवल दो शोधकर्ताओं का चयन हुआ है, जिनमें सिद्धांत एक हैं। वे अपने पीएचडी शोध कार्य का मार्गदर्शन प्रोफेसर अजय कुमार आर्य (भूविज्ञान विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय) और डॉ. साधन कुमार बासुमतारी, वैज्ञानिक 'ई', बिरबल साहनी पुराविज्ञान संस्थान से प्राप्त कर रहे हैं।

HINDUSTAN TIMES PAGE NO 6

More infra investment crucial for UP dev: Study

HT Correspondent
letters@htlive.com

Karuna S Kannaujia and (right) Nagendra K Maurya

LUCKNOW: A recent study by faculty members at Lucknow University, in collaboration with 16th Finance Commission, has provided various suggestions for financial growth in the state. It was prepared by Nagendra Kumar Maurya and Karuna Shanker Kannaujia after in-depth study of finances of the state between 2012-13 and 2023-24. Their suggestions will help the commission make final recommendations.

The study found that although UP made progress in increasing its tax revenue, the overall tax-to-GDP ratio remains low between 7-8%. "While the introduction of GST improved tax structure and collection efficiency, the dependence on central transfers continues. Besides, the non-tax revenues, such as fees and dividends, grew slower after the pandemic, showing the need for diversified income sources," said Maurya.

The study emphasised that the capital expenditure rose to nearly 28% of total spending in 2023-24, which indicates growing attention to infrastructure, schools, and hospitals. However, revenue expenditure, particularly on salaries and subsidies continues to have the major share of the budget.

"We suggest improvise cost recovery in public services and ensuring that loans and advances are directed toward productive assets. For the power sector, inefficiencies and cross-subsidisation continue to affect fiscal stability for which transparent tariff structures, reduction in technical losses and performance-based management in the Uttar Pradesh Power Corporation Ltd (UPPCL) is recommended," said Maurya.

They also shared that there is a need for stronger monitoring mechanisms, improved data transparency and regular updating of public financial records while fiscal discipline, data transparency, and efficient public spending are key to strengthening a state's financial health.

"Enhanced infrastructure investment, industrial growth and local governance reforms will be crucial for sustainable and inclusive development, which can help the state in contributing to the country's trillion-dollar economy vision," said Kannaujia.

TOI PAGE NO 4

LU profs chart path to fiscal strength for UP

Times News Network

Lucknow: Lucknow University's Applied Economics associate professor Nagendra Kr Maurya and assistant professor Karuna Shanker Kannaujiya have evaluated the state's finances and recommended measures to improve Uttar Pradesh's financial health. The task was assigned to the two faculty members by the 16th Finance Commission to assist in strengthening the state's fiscal position.

The report prepared by the duo, titled 'Evaluation of Finances of the State of Uttar Pradesh,' examines how Uttar Pradesh managed its finances from 2012-13 to 2023-24. It broadly analyses the state's tax revenue, expenditure, power sector, and local governance. Overall, the report emphasises the importance of fiscal discipline, transparent data, and efficient spending to improve Uttar Pradesh's financial health. It further highlights that investing in infrastructure, boosting industrial growth, and reforming local governance are crucial for sustainable development and for helping the state contribute to India's trillion-dollar economy goal.

"Uttar Pradesh has increased its tax revenue, but it still accounts for only 7-8% of the state's total economic output (GSDP). The introduction of GST has helped improve tax collection, but the state continues to rely heavily on funds from the central govt. Non-tax revenues, such as fees and dividends, have grown slowly since the pandemic, indicating a need for more diverse income sources," said Nagendra.

He added that the state is spending more on infrastructure, education, and healthcare, with capital investment accounting for 28% of total expenditure in 2023-24.

VOL PAGE NO 3

लविवि के अर्थशास्त्रियों ने तैयार की 16वें वित्त आयोग के लिए अहम सिफारिशें

लखनऊ। लखनऊ विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्रियों डॉ. नागेन्द्र कुमार मौर्य और डॉ. करुणा शंकर कनौजिया द्वारा तैयार की गयी एप्लूएशन ऑफ फाइनेंस ऑफ द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश शीर्षक वाली विस्तृत रिपोर्ट ने वर्ष 2012-13 से 2023-24 के बीच उत्तर प्रदेश की वित्तीय स्थिति का गहन विश्लेषण प्रस्तुत किया है। यह अध्ययन 16वें वित्त आयोग के प्रयोजन में किया गया है, जिसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश की वित्तीय व्यवस्था में सुधार के लिए ठोस सिफारिशें देना है। इन सिफारिशों के आधार पर 16वां वित्त आयोग अपने अंतिम निर्णय तैयार करेगा। बता दें कि उत्तर प्रदेश अब तक वित्त आयोग की अनुशंसाओं से सार्वजनिक लाभ प्राप्त करने वाला राज्य रहा है और यह रिपोर्ट आयोग को राज्य के लिए हस्तांतरण की राशि तय करने में मदद करेगी। रिपोर्ट के अनुसार, उत्तर प्रदेश ने कर संग्रहण में प्रगति की है, लेकिन कर-से-राज्य सकल घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) अनुपात अभी भी लगभग 7-8 प्रतिशत के आसपास सीमित है। वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू होने से कर संरचना और वसूली की दक्षता में सुधार हुआ है, किंतु राज्य की केंद्रीय अनुदानों पर निर्भरता बनी हुई है। गैर-कर राजस्व जैसे शुल्क, लाभांश आदि महामारी के बाद धीमी गति से बढ़े हैं, जिससे आय के विविध स्रोत विकसित करने की आवश्यकता स्पष्ट होती है। व्यय के मोर्चे पर रिपोर्ट में यह पाया गया है कि पूंजीगत निवेश में सकारात्मक वृद्धि हुई है। वर्ष 2023-24 में कुल व्यय में पूंजीगत खर्च का हिस्सा बढ़कर लगभग 28 प्रतिशत तक पहुंच गया है। यह संकेत देता है कि सरकार ने बुनियादी ढांचे, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया है। हालांकि, राजस्व व्यय विशेषकर वेतन और सब्सिडी पर खर्च अभी भी बजट का बड़ा हिस्सा है। रिपोर्ट सुझाव देती है कि सार्वजनिक सेवाओं में लागत वसूली को बेहतर बनाया जाए। रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड में प्रदर्शन-आधारित प्रबंधन लागू करने की सिफारिश की है। स्थानीय स्तर पर रिपोर्ट में पाया गया है कि पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों के पास सीमित वित्तीय स्वायत्तता है और वे वित्त आयोग से प्राप्त अनुदानों का पूर्ण उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। रिपोर्ट ने इन संस्थाओं के लिए बेहतर निगरानी प्रणाली, डेटा पारदर्शिता और वित्तीय अभिलेखों के नियमित अद्यतन की आवश्यकता पर बल दिया है। रिपोर्ट के अनुसार, राजकोषीय अनुशासन, डेटा की पारदर्शिता और कार्यात्मक व्यय की दक्षता उत्तर प्रदेश की वित्तीय सेहत को मजबूत करने की कुंजी हैं। बुनियादी ढांचा निवेश, औद्योगिक विकास और स्थानीय शासन में सुधार से राज्य सतत और समावेशी विकास की दिशा में आगे बढ़ सकेगा – जिससे भारत के ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था के लक्ष्य में उत्तर प्रदेश की भागीदारी और सशक्त होगी।

HINDUSTAN PAGE NO 7

| चिंताजनक | लखनऊ विश्वविद्यालय के एपी सेन सभागार में विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस पर जागरूकता कार्यक्रम में वक्ताओं ने रखे विचार

'मोबाइल का ज्यादा प्रयोग आधुनिक बीमारी'

लखनऊ, संवाददाता। लखनऊ विवि के एपी सेन सभागार में विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस पर लापंस इंटरनेशनल 321-बी: लखनऊ, कजीएमयू के मनोरोग विभाग की ओर से मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण पर जागरूकता कार्यक्रम और पैनल चर्चा का आयोजन हुआ। मुख्य अतिथि चिकित्सक डॉ. नीरज बोरा ने मनोविज्ञान को युवा का सबसे अधिक मांग वाला विभाग बताया। उन्होंने मोबाइल फोन के ज्यादा इस्तेमाल को एक बड़ी आधुनिक बीमारी बताया। इससे निपटने के लिए उपकरणों को बंद करके परिवार के साथ चर्चा का एक घंटा समर्पित करने का सुझाव दिया। डीजी डॉ. अहरसी सिंह ने कहा कि दूसरों के लिए जीने के बजाय स्व-केंद्रित जीवनशैली और शिक्षा प्रणाली में बदलाव ने मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों को बढ़ाया है, जो 50 साल पहले कम थे।

विश्वविद्यालय में विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

आयोजन सचिव डॉ. निशांत रंजा ने बताया कि कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य मानसिक स्वास्थ्य पुनर्नीतियों के बढ़ते वैश्विक मुद्दे, कलंक को समाप्त करने की जरूरत और समग्र कल्याण के नजरिए को अपनाने पर ध्यान केंद्रित करना था। इसमें युवाओं की ओर वापसी पर जोर दिया गया। लायंस क्लब इंटरनेशनल की सदस्य डॉ. निधि नागर समेत कई अन्य उपस्थित रहे।

मानसिक स्वास्थ्य पर पैनल चर्चा में निकले कई तथ्य : कार्यक्रम में सात पैनलिस्टों वाली एक पैनल चर्चा हुई। इसमें सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति शम्भोगुल हसनैन ने मानसिक स्वास्थ्य के कानूनी पहलुओं और समाज में अस्वीकृति की महत्वपूर्ण चुनौतियों पर बात की।

मानसिक रोगी डॉक्टर से मिलें

लखनऊ। अभी भी लोग मानसिक बीमारियों को छिपाते हैं। डॉक्टर के पास जाने से पहले बाबा और ओझा के पास जाते हैं। समय पर डॉक्टर से इलाज कराकर मानसिक बीमारी पर काबू पाया जा सकता है। यह सलाह केजीएमयू मानसिक स्वास्थ्य विभाग के डॉ. अदर्श त्रिपाठी ने दी। डॉ. आदर्श त्रिपाठी ने कहा कि समय पर सटीक इलाज से मानसिक बीमारियां काबू में आ सकती हैं।

60% को इलाज नहीं मिलता

लखनऊ। लोहिया संस्थान के निदेशक डॉ. नीरज सिंह ने कहा कि मानसिक बीमारियां तेजी से बढ़ रही हैं। मरीजों की संख्या के मुकाबले संसाधनों की कमी है। यही मरीज भी मानसिक रोगियों को अस्पताल तक ले पहुंचते हैं। यही वजह है कि 60 से 65% मानसिक रोगियों को उचित इलाज नहीं मिल पाता है। बालरामपुर में हुई गोष्ठी में डॉ. देवाशीष सुहाना ने कहा कि मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना जरूरी है।

AMRIT VICHAR PAGE NO 2

प्रदेश की वित्तीय स्थिति पर रिपोर्ट तैयार

लविवि शिक्षकों ने वर्ष 2012 से 24 तक का किया विश्लेषण

कार्यालय संवाददाता, लखनऊ

अमृत विचार : लखनऊ विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्रियों डॉ. नागेंद्र कुमार मौर्य और डॉ. करुणा शंकर कनौजिया द्वारा तैयार रिपोर्ट में वर्ष 2012-13 से 2023-24 तक उत्तर प्रदेश की वित्तीय स्थिति का गहन विश्लेषण किया गया है। यह अध्ययन 16वें वित्त आयोग के प्रयोजन में किया गया है, जिसका उद्देश्य राज्य की वित्तीय व्यवस्था में सुधार के लिए ठोस सिफारिशें देना है। रिपोर्ट में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश अब तक सार्वजनिक लाभ प्राप्त करने वाला राज्य रहा है और यह रिपोर्ट आयोग को राज्य के लिए हस्तांतरण की राशि तय करने में मदद करेगी। रिपोर्ट के अनुसार, उत्तर प्रदेश ने कर संग्रहण में प्रगति की है, लेकिन कर-से-राज्य सकल घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) अनुपात अभी भी लगभग 7-8 प्रतिशत के आसपास सीमित है। वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू होने से कर संरचना और वसूली की दक्षता में सुधार हुआ है, किंतु राज्य की केंद्रीय अनुदानों पर निर्भरता बनी हुई है। गैर-कर राजस्व जैसे शुल्क, लाभांश आदि महामारी के बाद धीमी गति से बढ़े हैं, जिससे आय के विविध स्रोत विकसित करने की आवश्यकता स्पष्ट होती है। पूंजीगत निवेश में सकारात्मक वृद्धि हुई है। वर्ष 2023-24 में कुल व्यय में पूंजीगत खर्च का हिस्सा बढ़कर लगभग 28 प्रतिशत तक पहुंच गया है। रिपोर्ट सुझाव देती है कि सार्वजनिक सेवाओं में लागत वसूली को बेहतर बनाया जाए।

• 16वें वित्त आयोग के लिए दी जाएंगी अहम सिफारिशें

आयोग को राज्य के लिए हस्तांतरण राशि तय करने में सहायक होगा।

रिपोर्ट के अनुसार, राज्य ने कर संग्रह में सुधार किया है, पर कर से राज्य सकल घरेलू उत्पाद अनुदान अभी भी 7-8 प्रतिशत के आसपास है। जीएसटी लागू होने से कर संरचना बेहतर हुई है, पर केंद्र पर निर्भरता बनी हुई है। गैर-कर राजस्व में महामारी के बाद वृद्धि धीमी रही है। व्यय के मोर्चे पर पूंजीगत निवेश में बढ़ोतरी हुई है- वर्ष 2023-24 में यह कुल व्यय का लगभग 28 प्रतिशत रहा, जिससे शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे पर सरकार का ध्यान स्पष्ट है। हालांकि वेतन और सब्सिडी पर खर्च अब भी अधिक है।

ऊर्जा क्षेत्र में लगातार डायनी और क्रॉस सब्सिडी की समस्या पर चिंता जताते हुए पारदर्शी टैरिफ और प्रदर्शन आधारित प्रबंधन लागू करने की सिफारिश की गई है। रिपोर्ट में स्थानीय निकायों की सीमित वित्तीय स्वायत्तता पर भी प्रकाश डाला गया है। लेखकों ने राजकोषीय अनुशासन, डेटा पारदर्शिता और व्यय दक्षता को राज्य की वित्तीय सेहत मजबूत करने की कुंजी बताया है।

HINDUSTAN PAGE NO 7

यूपी में बुनियादी ढांचे पर बढ़ा फोकस

लखनऊ। लखनऊ विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र विभाग के डॉ. नागेंद्र कुमार मौर्य और डॉ. करुणा शंकर कनौजिया ने उत्तर प्रदेश राज्य के वित्त का मूल्यांकन विषय पर रिपोर्ट तैयार की है। इसमें बताया गया है कि राज्य ने कर संग्रहण में सुधार किया है, लेकिन कर से जीएसडीपी अनुपात अब भी सात से आठ फीसदी के बीच है। पूंजीगत निवेश बढ़कर कुल व्यय का लगभग 28 प्रतिशत हो गया है, जिससे वित्तीय योजना में बुनियादी ढांचे, शिक्षा और स्वास्थ्य पर फोकस बढ़ा है। यह अध्ययन 16वें वित्त आयोग के लिए किया गया है। इसमें वर्ष 2012-13 से 2023-24 तक की वित्तीय स्थिति का विश्लेषण किया गया है।

DAINIK JAGRAN PAGE NO 36

कर नीति में सुधार से बढ़ा सकते हैं राजस्व

जागरण संवाददाता • लखनऊ : उत्तर प्रदेश में आय के साथ-साथ खर्च भी बढ़ रहा है। ऐसे में कर नीति में सुधार करके राजस्व बढ़ा सकते हैं। या फिर नई सुविधाएं देकर भी इसमें वृद्धि संभव है। साथ ही बुनियादी ढांचा निवेश, औद्योगिक विकास और स्थानीय शासन में सुधार से राज्य सतत और समावेशी विकास की दिशा में आगे बढ़ सकता है। इसके अलावा 2047 में विकसित भारत बनाने के लिए अहम भूमिका निभाने वाले प्रदेश में राजस्व संबंधी नीतियों को पुनः निर्धारित करने की जरूरत है। यह सुझाव लखनऊ विश्वविद्यालय के व्यावहारिक अर्थशास्त्र विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डा. नागेंद्र कुमार मौर्य और असिस्टेंट प्रोफेसर डा. करुणा शंकर कनौजिया की ओर से तैयार की गई 'उत्तर प्रदेश राज्य के वित्त का मूल्यांकन' शीर्षक वाली विस्तृत रिपोर्ट ने दिए गए हैं।

असिस्टेंट प्रोफेसर करुणा शंकर कनौजिया ने बताया कि 16वें वित्त आयोग ने अक्टूबर 2024 में साढ़े छह लाख रुपये का शोध प्रोजेक्ट दिया था। यह भी बताया था कि वर्ष 2012-13 से 2023-24 के बीच उत्तर प्रदेश की वित्तीय स्थिति में किन किन बिंदुओं पर अध्ययन करना है। यह शोध अध्ययन 16वें वित्त आयोग के प्रयोजन में किया गया है, जिसका उद्देश्य उप्र की वित्तीय व्यवस्था में सुधार के लिए ठोस सिफारिशें देना है। रिपोर्ट के अनुसार, उत्तर प्रदेश ने कर संग्रहण करने में प्रगति की है, लेकिन कर से राज्य सकल घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) अनुपात अभी भी लगभग सात से आठ प्रतिशत के आसपास सीमित है। वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू होने से कर संरचना और वसूली की दक्षता में सुधार हुआ है। फिर भी राज्य की केंद्रीय अनुदानों पर निर्भरता बनी हुई है। गैर-कर राजस्व जैसे शुल्क, लाभांश आदि महामारी के बाद धीमी गति से बढ़े हैं, जिससे आय के विविध स्रोत विकसित करने की आवश्यकता स्पष्ट होती है। पूंजीगत निवेश में सकारात्मक वृद्धि हुई है। वर्ष 2023-24 में कुल व्यय में पूंजीगत खर्च का हिस्सा बढ़कर लगभग 28 प्रतिशत तक पहुंच गया है। रिपोर्ट सुझाव देती है कि सार्वजनिक सेवाओं में लागत वसूली को बेहतर बनाया जाए।

डा. नागेंद्र मौर्य, डा. करुणा शंकर कनौजिया

ऊर्जा क्षेत्र की चुनौतियां

विद्युत क्षेत्र में अक्षमताएं और क्रास-सब्सिडी की समस्या अब भी वित्तीय स्थिरता को प्रभावित कर रही है। स्थानीय स्तर पर पाया गया है कि पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों के पास सीमित वित्तीय स्वायत्तता है। वे वित्त आयोग से प्राप्त अनुदानों का पूर्ण उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। रिपोर्ट ने इन संस्थाओं के लिए बेहतर निगरानी प्रणाली, डेटा पारदर्शिता और वित्तीय अभिलेखों के नियमित अद्यतन की आवश्यकता पर बल दिया है।

शोध छात्र सिद्धांत करेंगे भारत का प्रतिनिधित्व

लखनऊ : लखनऊ विश्वविद्यालय के भू विज्ञान विभाग के शोधार्थी एवं बिरबल साहनी पुराविज्ञान संस्थान में काम कर रहे शोध छात्र सिद्धांत को द माइक्रोपैलियोलॉजिकल सोसाइटी (टीएमएस) की ओर से प्रतिष्ठित ट्रैवल ग्रांट 2025 से सम्मानित किया गया है। वे इटली के यूनिवर्सिटी आफ पिसा में आयोजित टीएमएस की वार्षिक बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। वहां काजीरंगा नेशनल पार्क के मोना झील में कण के आकार और परागकण संचयन का पैटर्न तथा इसका प्राचीन पर्यावरण और प्राचीन बाढ़ विश्लेषण पर प्रभाव विषय पर अपना शोध प्रस्तुत करेंगे। वि.

डा. हेमेंद्र कुमार सिंह बने नोडल अधिकारी

जासं • लखनऊ : लखनऊ विश्वविद्यालय की कुलपति प्रो. मनुका खन्ना ने शिक्षा शास्त्र विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डा. हेमेंद्र कुमार सिंह को चतुर्थ राष्ट्रीय पर्यावरण युवा संसद (एनईवाइपी)-2026 के आयोजन के लिए पर्यावरण नोडल अधिकारी नामित किया गया है। डा. हेमेंद्र ने बताया कि जनवरी 2026 में नागपुर में होने वाला यह आयोजन वसुधैव कुटुंबकम के मोटो और ग्रीन यूथ लीडरशिप की भावना के साथ आयोजित किया जाएगा। इस प्रतियोगिता में जल, जंगल, जमीन, जानवर और जन विषयों पर विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों एवं संबद्ध पांचों जिलों लखनऊ, रायबरेली, सीतापुर, लखीमपुर खीरी और हरदोई के कालेजों के शिक्षार्थी प्रतिभाग करेंगे। इसके लिए कुलपति ने निर्देश जारी किए हैं।

डा. हेमेंद्र कुमार सिंह